



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 14, 1975/ज्येष्ठ 24, 1897  
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14, 1975/JYAISTHA 24, 1897

इस भाग में बिम्ब पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities  
(other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1975

के या किसी राज्य की विधान-सभाधान सभा/विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित घोषित करता है।

[सं० उड़ीसा/वि० सा०/120/74]

क्र० आ० 1796.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1974 में हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिये कामख्या नगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार डा० बिनायक मिश्र, ग्राम टिपिलाई, पो० आ० सुरप्रतापपुर, जिला धेन-कनाल (उड़ीसा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्घीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस सफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त डा० बिनायक मिश्र को संसद के किसी भी सदस्य

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1975

S.O. 1796.—Whereas the Election Commission is satisfied that Dr. Binayak Misra, Village—Tipilai, P.O.—Surapratapur, District Dhenkanal (Orissa), a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from Kamakhyanagar constituency, held in February, 1974 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10 A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Dr. Binayak Misra to be disqualified for being chosen as, and for

being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/120/74]

आदेश

20 मई, 1975

का० प्रा० 1797.—यत्न, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 273 बरीडीह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगदम्ब प्रसाद भगत, बाघडीह, हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पर्क सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायोजित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जगदम्ब प्रसाद भगत को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार वि० सं०/273/72(191)]

ए० एन० सैन, सचिव

## ORDER

New Delhi, 20th May, 1975

S.O. 1797.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagdamba Prasad Bhagat, Village & P. O. Baudhdih, Hazaribagh, who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 273-Jaridh constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagdamba Prasad Bhagat to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/273/72(191)]

A. N. SEN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और वीमा विभाग)

आय-कर और धन-कर

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1975

का० प्रा० 1798.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 ठ की उपधारा (1) के खण्ड

(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 1975 और 31 मार्च, 1977 के बीच जारी किए गए 6 प्रतिशत 10 वर्षीय बंधपत्र 1985 को उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 867 (फा० सं० 178/15/75-आई टी ए आई)]

सी०सी० गणपती, अपर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

INCOME-TAX AND WEALTH-TAX

New Delhi, the 10th April, 1975

S.O. 1798.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 80 L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the 6 per cent 10 years Bonds 1985 issued by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. Between the 1st April, 1975 and the 31st March, 1977, for the purposes of said clause.

[No. 867 (F. No. 178/15/75-IT. A1)]

C. C. GANAPATHY, Additional Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1975

(आयकर)

का० प्रा० 1799.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सर्वश्री डी०एम० जोशी और पी० एल० भट्ट को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना सं० 760 (फा० सं० 404/260/74-आई टी सी सी), तारीख 21 अक्टूबर, 1974 और अधिसूचना सं० 190 (फा० सं० 404/274/72-आई टी सी सी) तारीख 18 सितम्बर, 1972 के अधीन की गई क्रमशः सर्वश्री बी० जी० बुच और एच०सी० शाह की नियुक्ति 1 मई, 1975 से रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना 1 मई, 1975 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 870 (फा० सं० 404/63/75-आई टी सी सी)]

New Delhi, the 15th April, 1975

## INCOME-TAX

S.O. 1799.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri D. M. Joshi and P. L. Bhatt, who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointment of S/Shri B. J. Buch and H. C. Shah, made under Notification No. 760 (F. No. 404/260/74-ITCC) dated the 21st October, 1974 and Notification No. 190 (F. No. 404/274/72-ITCC) dated the 18th September, 1972 respectively are hereby cancelled with effect from the 1st May, 1975.

3. This Notification shall come into force with effect from the 1st May, 1975.

[No. 870 (F. No. 404/63/75-ITCC)]

का० प्रा० 1800.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सर्वश्री पी० एन० नेमाडे, पी० एम० लोकर, बी० एन० बानी, एम० पी० कोतवाल, एस० डी० मडाले और एम० बी० साठे को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2 अधिसूचना सं० 588 (फा० सं० 404/108/74-आई टी सी) तारीख 9 अप्रैल, 1974 के अधीन की गई सर्वश्री एस० एस० नारवेकर, पी० वी० असेरकर, एम० डी० रोकडे और बी० भार० लोकर, अधिसूचना सं० 330 (फा० सं० 404/124/73-आई टी सी) तारीख 18 अप्रैल, 1973 के अधीन की गई श्री डी० आर० आटे और अधिसूचना सं० 349 (फा० सं० 404/124/73-आई टी सी) तारीख 11 मई, 1973 के अधीन की गई श्री के० पी० पन्डारकर की नियुक्ति 1 मई, 1975 से रद्द की जाती है।

3 यह अधिसूचना 1 मई, 1975 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 872 (फा० सं० 404/61/75-आई टी सी)]

टी० आर० अगवाल, उप सचिव

S.O. 1800.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri P. N. Nemade, P. M. Laukar, V. N. Wani, M. P. Kotwal, S. D. Madhale and M. V. Sathe who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointment of S/Shri S. S. Narvekar, P. V. Aserkar, M. D. Rokade and V. R. Lokar made under Notification No. 588 (F. No. 404/108/74-ITCC) dated the 9th April, 1974, Shri D. R. Apte made under Notification No. 330 (F. No. 404/124/73-ITCC) dated the 18th April, 1973 and Shri K. P. Pandharkar made under Notification No. 349 (F. No. 404/124/73-ITCC) dated the 11th May, 1973 are hereby cancelled with effect from the 1st May, 1975.

3. This Notification shall come into force with effect from the 1st May, 1975.

[No. 872 (F. No. 404/61/75-ITCC)]

T. R. AGGARWAL, Dy. Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड

नई दिल्ली, 2 जुलाई 1973

का० प्रा० 1801.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 273 (फा० सं० 261/41/73-आई० टी० जे०) तारीख 29-1-73 के उपबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

उक्त अनुसूची में क्रम सं० 2 के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जायगा और विद्यमान क्रम सं० 3 से 8 को क्रमशः 2 से 7 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा।

उक्त अनुसूची में जालधर रेंज में स्तम्भ 3 में निम्नलिखित का लोप किया जायेगा,

2 केन्द्रीय सकल जनका मुख्यालय लुधियाना में है और क्रम सं० 3 और 4 की प्रविष्टियों की क्रम सं० 2 और 3 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

यह अधिसूचना 2-7-73 से प्रभावी होगी।

[सं० 410 (फा० सं० 261/4/73-आई० टी० जे०)]

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 2nd July, 1973

### INCOME-TAX

S.O. 1801.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 122 of the I. T. Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its notification No. 273 (F. No. 261/4/73-ITJ) dated 29-1-1973 viz.---

In the said Schedule entries against Sr. No. 2 shall be deleted and the existing Sr. Nos. 3 to 8 shall be renumbered as 2 to 7 respectively.

In the said schedule from Jullundur Range, in Column 3 the following shall be deleted;

"2. Central Circles having headquarters at Ludhiana" and the entries at S. Nos. 3 & 4 thereof shall be renumbered as S. Nos. 2 & 3.

This notification shall take effect from 2-7-1973.

[No. 410 (F. No. 261/4/73-ITJ)]

नई दिल्ली, 14 अगस्त 1973

का० प्रा० 1802.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में बोर्ड की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं संख्या 98 (फा० सं० 261/17/72-आई० टी० जे०) तारीख 31 मई 1972 और सं० 234 (फा० सं० 261/17/72-आई० टी० जे०) तारीख 30 नवम्बर, 1972 को आंशिक उपांतरण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर प्रायुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर मकिलों में आयकर या अधिकर के निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

## अनुसूची

रेंज	आयकर सिकल और आयकर अधिकारी
2. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), बंगलौर रेंज, (मुख्यालय) बंगलौर।	1. सिकल-1, बंगलौर 2. कोलार सिकल 3. तुमकुर सिकल
3. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), मैसूर रेंज, (मुख्यालय) मैसूर।	1. सिकल II बंगलौर 2. मैसूर सिकल 3. उदीपी सिकल 4. मंगलौर सिकल 5. कुर्ग सिकल 6. मण्ड्या सिकल 7. चन्नापटना सिकल 8. बंगलौर सिकल (पुराना) के आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के अधीन पारित किये गये आदेशों की बाबत। 9. विशेष सर्वेक्षण सिकल बंगलौर 10. हसन सिकल 11. चिकमगलूर सिकल 12. बेतन सिकल 13. शिमोगा सिकल
4. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), पंजी रेंज (मुख्यालय) पंजी, गोवा।	1. मार्गोव सिकल 2. पंजी सिकल 3. बेलगांव सिकल 4. बीजापुर सिकल 5. बागलकोट सिकल
5. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), धारवाड़ रेंज (मुख्यालय) हुबली।	1. हुबली रेंज 2. धारवाड़ सिकल 3. गदाग सिकल 4. करवाड़ सिकल 5. हासपेट सिकल 6. बेलरी सिकल 7. रायचूर सिकल 8. गुलबर्गा सिकल 9. चित्रदुर्ग सिकल 10. दावरमगीर सिकल

यह अधिसूचना 20-8-73 से प्रभावी होगी।

[सं० 435/फा० सं० 261/20/73-आई०टी०जे०]

New Delhi, 14th August, 1973

S. O. 1802.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of Board's Notification No. 98 (F. No. 261/17/72-ITJ) dated 31st May, 1972 and No. 234 (F. 261/17/72-ITJ) dated 30th November 1972, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in Column (1) of the schedule below shall perform their

functions in respect of all persons and incomes assessed to tax or Supertax in the Income-tax circles by the Income tax Officers specified in the corresponding entry in column (2) thereof :—

## SCHEDULE

Range	Income-tax circles and Income-tax Officers
1	2
2. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bangalore Range, (HQ) Bangalore.	1. Circle-I, Bangalore. 2. Kolar Circle. 3. Tumkur Circle.
3. Appellate Assistant Commissioner of Income tax, Mysore Range, (HQ) Mysore.	1. Circle-II, Bangalore. 2. Mysore Circle. 3. Udupi Circle. 4. Mangalore Circle. 5. Coorg Circle. 6. Mandya Circle. 7. Channapatna Circle. 8. In respect of orders passed under the Income-tax Act, by the I.T.O.'s of Bangalore Circle (Old). 9. Special Survey Circle Bangalore-I. 10. Hassan Circle. 11. Chickmagalur circle. 12. Salary Circle. 13. Shimoga Circle.
4. Appellate Assistant Commissioner of Income Tax Panaji Range, (HQ) Panaji (Goa).	1. Margoa Circle. 2. Panaji Circle. 3. Belgaum Circle. 4. Bijapur Circle. 5. Bagalkot Circle.
5. Appellate Assistant Commissioner of Income Tax Dharwar Range, (HQ) Hubli.	1. Hubli Circle. 2. Dharwar Circle. 3. Gadag Circle. 4. Karwar Circle. 5. Hospot Circle. 6. Bellary Circle. 7. Raichur Circle. 8. Gulbarga Circle. 9. Chitradurga Circle. 10. Davanagore Circle.

This Notification shall take effect from 20-8-73.

[No. 435 (F. No. 261/20/73-ITJ)]

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1973

फा० प्रा० 1803.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में बोर्ड की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं० 123 (फा० सं० 261/9/72-आई०टी०जे०) तारीख 26 जून, 1972 का आंशिक उपांतरण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ

3 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सर्किलों, बोर्डों और जिलों में आयकर या अधिकार से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 22-8-73.

[No. 441 (F. No. 261/5/73-ITJ)]

अनुसूची

क्र० सं०	रेंज	आय-कर सर्किल, बोर्ड और जिले
17.	विशेष रेंज-XIII-मुम्बई	1. आयकर अधिकारियों के प्रभार-धीन कंपनी सर्किल-III(1) से III(7) । 2. कंपनी सर्किल-VI में सभी आयकर अधिकारी ।

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, बोर्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज की अंतरित हो गया हो वहाँ उस आय-कर सर्किल, बोर्ड या जिले या उसके किसी भाग में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, बोर्ड या जिला या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसकी उक्त सर्किल, बोर्ड या जिला या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अंतरित कर दी जायेगी और उनके संबंध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना 28-3-73 से प्रभावी होगी ।

[सं० 441 (फा० सं० 261/5/73-आई०टी०जे)]

New Delhi, 22nd August, 1973

S. O. 1803.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of the Board's Notification No. 123 (F. No. 261/9/72-ITJ) dated 26th June, 1972 in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (2) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (3) thereof :

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Ward/Cir. & District
17.	Special Range-XIII, Bombay.	(1) Companies Circle-III (1) to III (7) ITOs Charges only. (2) All I.T.O.s. in Companies Circle-VI.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeal as arising out of assessments made in that Income tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification shall take effect be transferred to and

शुद्धि पत्र

आयकर

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1973

फा० प्रा० 1804.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना [सं० 436 (फा० सं० 261/8/73-आई०टी०जे)] तारीख 16-8-73 की अनुसूची में निम्नलिखित शुद्धि की जायेगी, अर्थात् :—

(1) 'घ रेंज नई दिल्ली' के सामने निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

1. जिला ii (7), (8), (8) (अतिरिक्त), 9, (9) (अतिरिक्त), (10), (11), 11 (अतिरिक्त), (12) और (12) (अतिरिक्त) नई दिल्ली ।

2. जिला iii (6), (6) (अतिरिक्त), (7) और (7) (अतिरिक्त) नई दिल्ली

(ii) 'इ रेंज, नई दिल्ली' के सामने निम्नलिखित रखा जायेगा :—

1. जिला 8(1), (2), (2) (अतिरिक्त), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (17), (19) और (19) (अतिरिक्त), नई दिल्ली ।

2. जिला-X(1), (2), (3), (4), (5), (6), नई दिल्ली ।

3. जिला viii बाई-क, क (अतिरिक्त), ख, ख (अतिरिक्त), ख (अतिरिक्त-i), ख (अतिरिक्त-ii), ग, घ, घ (i), इ और च, नई दिल्ली ।

4. क-i, क-ii, क-iii क-iv, क-iii(1) और 1(1) जिले, नई दिल्ली ।

5. आयकर-एवं-धनकर सर्किल-viii, नई दिल्ली ।

6. विशेष सर्किल-III, नई दिल्ली ।

[सं० 450 (फा० सं० 261/8/73-आई०टी०जे)]

सी० बी० पद्मनाभन, अवर सचिव

New Delhi, the 28th August, 1975

CORRIGENDUM

S.O. 1804.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the following correction shall be made in the Schedule to its Notification No. 436 (F. No. 261/8/73-ITJ) dated 16-8-1973 viz.—

(I) Against 'D' Range, New Delhi following shall be substituted:—

1. District II (7), (8), (8) (Addl.), (9), (9) (Addl.) (10), (11), (11) (Addl.), (12) and (12) (Addl.), New Delhi.
2. District III (6), (6) (Addl.), (7) and (7) (Addl.) New Delhi.

(II) Against 'E' Range, New Delhi following shall be substituted:—

1. District VIII (1), (2), (2) (Addl.), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (17), (19) and (19) (Addl.), New Delhi.
2. District X(1), (2), (3), (4), (5), (6), New Delhi.
3. District VIII Wards-A, A(Addl.), B, B(Addl.), B(Addl.-I), B(Addl.-II), C, D, D(I), E and F, New Delhi.
4. A-I, A-II, A-III, A-IV, A-IV(I) and I(I) Districts, New Delhi.
5. Income-tax-cum-Wealth Tax Circle-VIII, New Delhi.
6. Special Circle-III, New Delhi.

[No. 450/F. No. 261/8/73-ITJ]

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1973

का० प्रा० 1805.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने पूर्ववर्ती आदेश सं० 102 (का० सं० 261/14/72-आई०टी०जे०) तारीख 2 जून, 1972 आंशिक उपान्त करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड निदेश देता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में मुजफ्फरपुर रेंज के अधीन का० सं० 4 में आयकर अधिकारी सर्वेक्षण, मुजफ्फरपुर उसके स्तम्भ 3 में मद (vi) के रूप में जोड़ा जायेगा और दरभंगा रेंज के अधीन का० सं० 3 में आयकर अधिकारी सर्वेक्षण, दरभंगा का लोप किया जायेगा।

यह अधिसूचना 1-10-1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 473/का० सं० 261/6/73-आई०टी०जे०]

New Delhi, the 19th September, 1973

S.O. 1805.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf and in partial modification of its earlier order No. 102 (F. No. 261/14/72-ITJ) dated the 2nd June, 1972 the Central Board of Direct Taxes hereby directs that in the Schedule annexed thereto in sl. 4 under Muzaffarpur Range, I.T.O. Survey, Muzaffarpur shall be added as item (vi) in column 3 thereof and that in sl. 3 under Darbhanga Range, I.T.O. Survey, Darbhanga shall be deleted.

This Notification shall take effect from 1-10-1973.

[No. 473/F. No. 261/6/73-ITJ]

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1973

का० प्रा० 1806.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में बोर्ड की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं० 435 (का० सं० 261/20 73-आई०टी०जे०) तारीख 14 अगस्त, 1973 का आंशिक उपान्तरण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर सर्किलों में आयकर या अधिकार से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

#### अनुसूची

रेंज	आयकर सर्किल, वार्ड और जिले
(1)	(2)
2. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), बंगलौर रेंज, बंगलौर, (मुख्यालय)	(1) सर्किल 1, बंगलौर (2) कोलार सर्किल. (3) तुमकुर सर्किल (4) न्यास सर्किल-एवं-विशेष अनुभाग, बंगलौर

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 477 (का० सं० 261/20/73-आई०टी०जे०)]

New Delhi, 27th September, 1973

S. O. 1806.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf and in partial modification of Board's notification No. 435 (F.No. 261/20/73-ITJ) dated 14th August, 1973 the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in column (1) of the Schedule below shall perform his function in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or supertax in the Income-tax Circles by the Income-tax Officers specified in the corresponding entry in column (2) thereof:—

#### SCHEDULE

Range 1	Income-tax Circles and Income-tax Officers
1.	2.
2. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bangalore Range, Bangalore. (HQ).	(1) Circle I, Bangalore. (2) Kolar Circle. (3) Tumkur Circle. (4) Trust Circle cum Foreign Section, Bangalore.

This Notification shall take effect from 1st October, 1973.

[No. 477 (F.No. 261/20/73-ITJ)]

नई दिल्ली, अक्टूबर 24 9173

क्रा० प्रा० 1807.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 395 (फा० सं० 261/11/73 आई० टी० जे०) तारीख 28-6-73 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची, क्रम सं० 3 और 8 में, सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जोधपुर रेंज, जोधपुर और बीकानेर रेंज, बीकानेर से पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेगी, अर्थात् :—

क्रम सं०	रेंज०	आयकर सर्किल/वार्ड और जिले
1	2	3
3. सहायक आयकर आयुक्त (अपील) जोधपुर रेंज, जोधपुर	1. क, ख और ग वार्ड, जोधपुर को अपवर्जित करते हुए जोधपुर के सभी आयकर वार्ड/सर्किल।	
	3. (क) बारमोर (ख) जालौर के सभी आयकर वार्ड/सर्किल	
8. सहायक आयकर आयुक्त (अपील) बीकानेर रेंज, बीकानेर,	1. (क) श्री गंगातगर (ख) बीकानेर (ग) नागौर (घ) चुरु (ङ) हनुमानगढ़ के सभी आयकर वार्ड/सर्किल	
	2. जोधपुर के क, ख और ग वार्ड।	

यह अधिसूचना 1-11-1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 489 फा० सं० 261/11/73-आई०टी०जे०]

New Delhi, the 24th October, 1973

S.O. 1807.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule to its Notification No. 395 (F.No. 261/11/73-ITJ) dated 28-6-73 viz :

In the said Schedule at Sr. No. 3 and 8 before Appellate Assistant Commissioners of Income-tax, Jodhpur Range, Jodhpur and Bikaner Range, Bikaner following entries shall be substituted namely :—

Item Range No.	Income-tax Circles/Wards and Districts.
3. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Jodhpur Range, Jodhpur.	1. All I.T. Wards/Circles at Jodhpur except A.B & C-Wards, Jodhpur.
	2. All I.T. Wards/Circles at (a) Barmer. (b) Jalore.

1

2

3

8. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bikaner Range, Bikaner.

1. All I.T. Wards/Circles at :  
(a) Sriganganagar.  
(b) Bikaner.  
(c) Nagaur.  
(d) Churu.  
(e) Hanumangarh.

2. A, B & C Wards at Jodhpur.

This Notification shall take effect from 1-11-1973

[No. 489 F. No. 261/11/73-ITJ]

नई दिल्ली, 9 नवम्बर 1973

क्रा० प्रा० 1808.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 370 (फा० सं० 261/13/73-आई० टी० जे०) तारीख 8-6-1963 से उपाख्य अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में केन्द्रीय रेंज ii, मुम्बई के सामने स्तम्भ 2 के अधीन खण्ड XXIII के पश्चात् खण्ड XXIV (केन्द्रीय) मुम्बई जोड़ा जायेगा :—

यह अधिसूचना 9-11-73 से प्रभावी होगी।

[सं० 496/फा० सं० 261/13/73-आई०टी०जे०]

सी० वी० पद्मनाभन, अवर सचिव

New Delhi, the 9th November, 1973

S.O. 1808.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its Notification No. 370 (F. No. 261/13/73-ITJ) dated 8-6-1973 viz.:

In the said Schedule against Central Range-II, Bombay under Column 2 after Section XXIII Section XXIV (Central) Bombay shall be added.

This Notification shall take effect from 9-11-1973.

[No. 496/F. No. 261/13/73-ITJ]

C. V. PADMANABHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल 1975

आदेश

क्रा० प्रा० 1809.—आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियाँ) नियम, 1962 के नियम 6 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, निर्देश देता है कि सर्वश्री पी० एन० नेमाडे, पी० एम० लोलकर, बी० एन० बानी एम० पी० कोतवाल, एस० डी० मङ्गले और एम० वी० साठे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

2 खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया था, महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित जिलों के संबंध में अधिकारिता का साथ साथ प्रयोग करेंगे :—

1. पुना
2. नासिक
3. थाना
4. कोलाबा
5. कोल्हापुर
6. सांगली
7. शोलापुर
8. अहमदनगर
9. जलगांव
10. दुलिया
11. सतारा
12. रत्नागिरी

2. सर्वश्री एस० एस० नारवेकर, पी० बी० अमेरकर, एम० बी० रोकाडे और बी० आर० लोकूर को आदेश सं० 589 (फा० सं० 404/108/74-आई० टी० सी० सी०) तारीख 9 अप्रैल, 1974 के अधीन श्री बी० आर० आटे को आदेश सं० 531 (फा० सं० 404/124/73-आई० टी० सी० सी०) तारीख 18 अप्रैल, 1973 के अधीन और श्री के० पी० पन्डारकर को आदेश सं० 350 (फा० सं० 404/124/73-आई० टी० सी० सी०) तारीख 11 मई, 1973 के अधीन प्रदत्त अधिकारिता 1 मई, 1975 से प्रत्याहृत की जाती है।

3. यह आदेश 1 मई 1975 से प्रवृत्त होगा।

[फा० सं० 404/61/75-आई० टी० सी० सी०]

टी० आर० अग्रवाल, सचिव

#### ORDER

New Delhi, the 15th April, 1975

**S.O. 1809.**—In pursuance of Rule 6 of the Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that S/Shri P. N. Nemade, P. M. Laukar, V. N. Wani, N. P. Kotwal, S. D. Madhale and M. V. Sathe authorised by the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), shall concurrently exercise jurisdiction in respect of the following districts in the State of Maharashtra:

1. Poona
2. Nasik
3. Thana
4. Kolaba
5. Kolhapur
6. Sangli
7. Sholapur
8. Ahmednagar

9. Jalgaon

10. Dhulia

11. Satara

12. Ratnagiri

2. The jurisdiction conferred upon S/Shri S. S. Narvkar, P. V. Aserkur, M. D. Rokade and V. R. Lokur made under Order No. 589 (F. No. 404/108/74-ITCC) dated the 9th April, 1974, Shri D. R. Apte made under Order No. 531 (F. No. 404/124/73-ITCC) dated the 18th April, 1973 and Shri K. P. Pandharkar made under Order No. 350 (F. No. 404/124/73-ITCC) dated the 11th May, 1973 is hereby withdrawn with effect from the 1st May, 1975.

3. This order shall come into force with effect from the 1st May, 1975.

[F. No. 404/61/75-ITCC]

T. R. AGGARWAL, Secy.

(Department of Banking)

New Delhi, the 31st May, 1975

#### CORRIGENDUM

**S.O. 1810.**—The date "15th December, 1975" appearing in the penultimate line of the English version of this Department's Notification No. 15 (5)-B. O. III/75 of 26th February, 1975 which was published in the Gazette of India—Part II—Section 3(ii) dated the 15th March, 1975, may be read as "13th December, 1975".

[No. 15 (5)-B. O. III/75]

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1975

**का०शा० 1811.**—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख के उपबन्ध बाड़ी दोघाब बैंक लिमिटेड, होशियारपुर पर 31 मार्च, 1976 तक लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15(25)-बी०ओ० 3/75]

मे० भा० उमगांवकर, अवर सचिव,

**S.O. 1811.**—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 10B of the said Act shall not apply to the Bari Doab Bank Ltd., Hoshiarpur, till the 31st March, 1976.

[No. 15(25)-B.O. III/75]

M. B. USGAONKAR. Under Secy.



## भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली, 30 मई, 1975

क्र० प्रा० 1812.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में मई, 1975 के 23 दिनांक को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा दृष्टि विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	48,83,77,000		सोने का सिक्का और बुलियन :-		
संचलन में नोट	66,05,96,93,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,58,000	
जारी किये गये कुल नोट		66,54,80,70,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
			विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,55,000
			रुपये का सिक्का		10,16,13,000
			भारत सरकार की रुपया प्रति-		
			भूतियां		63,40,38,02,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे		
			वाणिज्य-पत्र		
कुल देयताएं		66,54,80,70,000	कुल आस्तियां		66,54,80,70,000

दिनांक : 28 मई, 1975

बी० बी० चारी, उप गवर्नर

23 मई, 1975 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	48,83,77,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	5,04,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	284,00,00,000	छोटा सिक्का	4,36,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :	
		(क) देशी	145,29,16,000
		(ख) विदेशी	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल	434,42,56,000
जमा राशियां :		विदेशों में रखा हुआ बकाया*	449,68,74,000
(क) सरकारी		निवेश**	336,98,29,000
(i) केन्द्रीय सरकार	57,88,07,000	ऋण और अग्रिम :—	
		केन्द्रीय सरकार की	
(ii) राज्य सरकारें	5,06,49,000	(ii) राज्य सरकारों को	400,21,08,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	518,07,77,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को @	293,73,05,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17,11,56,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को @ @	318,17,35,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,50,45,000	(3) दूसरों को	40,19,70,000
(iv) अन्य बैंक	49,27,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
		ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,79,46,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	13,61,04,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	70,70,00,000

देयताएं	रुपये	प्रास्तियां	रुपये
(ग) अन्य . . . . .	770,94,76,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश . . . . .	10,77,46,000
देय बिल . . . . .	129,53,01,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और प्रग्रिम . . . . .	46,92,96,000
अन्य देयताएं . . . . .	919,08,86,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और प्रग्रिम . . . . .	264,64,56,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से . . . . .	274,61,66,000
		ऋण, प्रग्रिम और निवेश . . . . .	
		(क) विकास बैंक को ऋण और प्रग्रिम . . . . .	264,64,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों . . . . .	
		में निवेश . . . . .	
		अन्य प्रास्तियां . . . . .	274,61,66,000
रुपये	3118,70,24,000	रुपये	3218,70,24,000

\*नकदी, अतिरिक्त जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

\*राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और प्रग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

@भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अन्वीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर प्रग्रिम दिये गये 176,87,00,000 रुपये शामिल हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और प्रग्रिम शामिल नहीं हैं।

[सं० एक० 10(1)/75 बी०प्रो० I]

दिनांक 28 मई, 1975

बी०वी० चारी, उप-गवर्नर

च० व० मीरजवाणी, प्रवर सचिव

#### RESERVE BANK OF INDIA

S.O. 1812.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 23rd day of May, 1975.

#### ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	48,83,77,000		Gold Coin and Bullion:—		
Notes in circulation	6605,96,93,000		(a) Held in India . . . . .	182,52,58,000	
Total notes issued	6654,80,70,000		(b) Held outside India . . . . .	..	
			Foreign Securities . . . . .	121,73,97,000	
			Total . . . . .	304,26,55,000	
			Rupce Coin . . . . .	10,16,13,000	
			Government of India Rupee . . . . .		
			Securities . . . . .	6340,38,02,000	
			Internal Bills of Exchange . . . . .		
			and other commercial paper . . . . .	..	
Total Liabilities	6654,80,70,000		Total Assets . . . . .	6654,80,70,000	

Dated the 28th of May 1975.

V. V. CHARI, Dy. Governor.

## Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 23rd May 1975.

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid up . . . . .	5,00,00,000	Notes . . . . .	48,83,77,000
Reserve Fund . . . . .	150,00,00,000	Rupee Coin . . . . .	5,04,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund . . . . .	284,00,00,000	Small Coin . . . . .	4,36,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund . . . . .	95,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund . . . . .	265,00,00,000	(a) Internal . . . . .	145,29,16,000
Deposits :—		(b) External . . . . .	
(a) Government		(c) Government Treasury Bills . . . . .	434,42,56,000
(i) Central Government . . . . .	57,88,07,000	Balances Held Abroad* . . . . .	449,68,74,000
(ii) State Governments . . . . .	5,06,49,000	Investments** . . . . .	336,98,29,000
(b) Banks		Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks . . . . .	518,07,77,000	(i) Central Government . . . . .	..
(ii) Scheduled State Co-operative Banks . . . . .	17,11,56,000	(ii) State Governments@ . . . . .	400,21,08,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks . . . . .	1,50,45,000	Loans and Advances to :—	
(iv) Other Banks . . . . .	49,27,000	(i) Scheduled Commercial Banks + . . . . .	293,73,05,000
(c) Others . . . . .	770,94,76,000	(ii) State Co-operative Banks†† . . . . .	318,17,35,000
Bills Payable . . . . .	129,53,01,000	(iii) Others . . . . .	40,19,70,000
Other Liabilities . . . . .	919,08,86,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to :—	
		(i) State Governments . . . . .	69,79,46,000
		(ii) State Co-operative Banks . . . . .	13,61,04,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks . . . . .	
		(iv) Agricultural Refinance Corporation . . . . .	70,70,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures . . . . .	10,77,46,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks . . . . .	46,92,96,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank . . . . .	264,64,56,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank . . . . .	
		Other Assets . . . . .	274,61,66,000
RUPEES . . . . .	3218,70,24,000	RUPEES . . . . .	3218,70,24,000

\* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

\*\* Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

+ Includes Rs. 176,87,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

†† Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 28th day of May 1975.

[No F 10(1)/75-BOI]  
V. V. CHARI, Dy. Governor.  
C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

## वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जून, 1975

का०प्रा० 1813—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०प्रा० 2789, तारीख 29 सितम्बर, 1973 के साथ प्रकाशित, अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन (संशोधक) नियम, 1975 है।

2. अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 के नियम 1 में “संशोधन नियम” शब्दों के स्थान पर “द्वितीय संशोधन नियम” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 1 (13)/73-ई आई एण्ड ई पी]

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th June, 1975

S.O. 1813.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Amendment Rules, 1973, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 2789, dated the 29th September, 1973, namely :—

1. These rules may be called the Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Amendment (Amending) Rules 1975.

2. In rule 1 of the Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Amendment Rules, 1973, for the words “Amendment Rules”, the words “Second Amendment Rules” shall be substituted.

[No. 1(13)/73-EI&amp;EP]

का०प्रा० 1814—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०प्रा० 2965 तारीख 6 अक्टूबर, 1973 के साथ प्रकाशित, अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन (द्वितीय संशोधक) नियम, 1975 है।

2. अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 के नियम 1 के उप-नियम (1) में, “संशोधन-नियम” शब्दों के स्थान पर, “द्वितीय संशोधन नियम” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 1 (13)/73-ई आई एण्ड ई पी]

S.O. 1814.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Amendment Rules, 1973, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 2965, dated the 6th October, 1973, namely :—

1. These rules may be called the Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Amendment (Second Amending) Rules, 1975.

2. In sub-rule (1) of rule 1 of the Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Amendment Rules, 1973, for the words “Amendment Rules”, the words “Third Amendment Rules” shall be substituted.

[No. 1(13)/73-EI&amp;EP]

का०प्रा० 1815—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कालीनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम कालीनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कालीनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973 में,—

(i) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“5. निरीक्षण का स्थान—इस नियम के प्रयोजन के लिए कालीनों का निरीक्षण या तो विनिर्माता के परिसरों पर किया जाएगा या निर्यातकर्ता के परिसरों पर और उन दोनों परिसरों पर निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में ऐसा निरीक्षण अभिकरण के परिसरों पर किया जाएगा।”

(ii) नियम 7 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने से अभिकरण के इन्कार करने से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा इस प्रकार इन्कार किए जाने की सूचना की प्राप्ति से दस दिन के भीतर ऐसे पैनेल को अपील कर सकेगा, जिसमें कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक सात ऐसे विशेषज्ञ होंगे, जो इन नियमों के अधीन अपीलों की सुनवाई और विनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

[सं० 1 (13)/73-ई आई एण्ड ई पी]

S.O. 1815.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following Rules to amend the Export of Carpets (Quality Control and Inspection) Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Carpets (Quality Control and Inspection) Amendment Rules 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Export of Carpets (Quality Control and Inspection) Rules, 1973,—

(i) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. Place of inspection.—Inspection of carpets for the purpose of this rule shall be carried out either at the premises of the manufacturer, or at the premises of the exporter, and in the absence of adequate facilities for inspection at both those premises, such inspection shall be carried out at the premises of the Agency." ;

(ii) in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4 may, within ten days of receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel consisting of not less than three, but not more than seven such experts as may be appointed by the Central Government for the purpose of hearing and deciding appeals under these rules."

[No. 1(13)/73-EI&EP]

का० प्रा० 1816:—बायु संपीड़कों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित व्यक्तियों को, उसके स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाले निर्यात निरीक्षण अधिकरणों के विनिश्चय के विरुद्ध उक्त नियमों के अधीन अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए, विशेषज्ञों के पैनल के रूप में नियुक्त करती है :—

परन्तु उक्त किसी भी पैनल का कोई सदस्य, जब किसी अपील की विषय वस्तु में वैयक्तिक रूप से हितबद्ध हो, उक्त अपील से संबंधित कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा।

#### सारणी

प्राधिकरण, जिनके विनिश्चय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। विशेषज्ञों का पैनल गठित करने वाले व्यक्ति जिसकी अपील की जा सकेगी।

1	2
असम, बिहार, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, राज्यों तथा मिजोरम तथा मंड्रान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अधिकरण-कलकत्ता और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर राज्यों तथा दिल्ली और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अधिकरण-दिल्ली।	1. निरीक्षण निदेशक कलकत्ता पदेन निरीक्षण सक्षम, पूति तथा निर्यात महा-निदेशालय, 1, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-13 2. गार्डेन रोच बर्कशाप, 43/46, गार्डेन रोच रोड, कलकत्ता-24 3. हालमैन क्लाइमेक्स मैनु-क्चरिंग लि०, 7ए, मिडलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-16 4. मे० के० जी० खोसला एंड कं०, 1, देशबन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली गैर-सदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक (पदेन), निर्यात निरीक्षण परिषद्, 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल) कलकत्ता-1

1	2	3
महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों तथा गोवा, दमण, दीव, दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अधिकरण, मुंबई	1. निरीक्षण निदेशक मुंबई (पदेन) निरीक्षण सक्षम पूति तथा निर्यात महा-निदेशालय प्रायकर भवन एनेक्सी, न्यू मैरीन लाइन्स, मुंबई अध्यक्ष	
एवं		
तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्यों तथा लक्षद्वीप मिनीकोय और अमिनदीवी द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाले निर्यात निरीक्षण अधिकरण-मद्रास तथा कोचीन।	2. मे० किलोस्कर न्यूमेटिक कं० (प्रा०) लि०, हादपसार इन्डस्ट्रियल एस्टेट, पूना 3. मे० इन्डरसोल-रैन्ड (इंडिया) लि०, 44, मोलाना अब्दुल गफार रोड, वरली, मुंबई 4. मे० कन्सालिडेटेड न्यूमेटिक टूल कं० (इंडिया) लि०, 321/302, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग मुंबई-400080	

#### गैर-सदस्य संयोजक

संयुक्त निदेशक निर्यात निरीक्षण परिषद्, अमन चौखर्सी, 113, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई-4।

2. पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

[सं० 6(37)/72-ई० एण्ड पी०]

के० बी० बालमुश्रमण्यन, उप-निदेशक

S. O. 1816—In pursuance of rule 7 of the Export of Air Compressors (Quality Control and Inspection) Rules, 1974, the Central Government hereby appoints the persons mentioned in column (2) of the Table given below as the panel of experts for the purpose of hearing appeals under the said rule against the decision of the Inspection Agencies carrying out inspection in the areas mentioned in corresponding entry in column (1) thereof :

Provided that where a member of any of the said panels is personally interested in the subject matter of any appeal, he shall not take part in the proceedings relating to that appeal.

#### TABLE

Authority against whose decision appeal lies	Persons constituting the panel of experts to which appeal lies
1	2
Export Inspection Agency-Calcutta carrying out inspection in the areas covered by the States of Assam, Bihar, Nagaland, Orissa, West Bengal, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and the Union Territories of Mizoram and the Andaman & Nicobar Islands.	1. Director of Inspection Ex-officio Calcutta Inspection Circle, Directorate General of Supplies & Disposals, 1, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13, Chairman 2. Garden Reach Workshops, 43/46, Garden Reach, Road, Calcutta-24. 3. Hallman Climax Manufacturing Ltd., 7A, Middleton Street, Calcutta-16.

(1)	(2)
Export Inspection Agency-Delhi carrying out inspection in the areas covered by the States of Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Union Territories of Delhi and Chandigarh.	4. M/s. K.G. Khosla & Co., 1, Deshbandhu Gupta Road, New Delhi.
	NON-MEMBER CONVENER.
	Joint Director, (Ex-officio), Export Inspection Council, 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.
Export Inspection Agency-Bombay carrying out inspection in the areas covered by the States of Maharashtra, Gujarat and Union Territories of Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli.	1. Director of Inspection (Ex-officio) Bombay Inspection Circle, Directorate General of Supplies & Disposals, Aayakar Bhavan Annexe, New Marine Lines, Bombay. ....Chairman
AND	2. M/s. Kirloskar Pneumatic Co. (P) Ltd., Hadaps Industrial Estate Poona.
Export Inspection Agency-Madras and Cochin carrying out inspection in the areas covered by the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh Kerala, Karnataka and Union Territories of Lakshadweep, Minicoy and Amindivi Islands.	3. M/s. Ingersoll-Rand (India) Ltd., 44, Moulana Abdul Gafar Road, Worli, Bombay.
	4. M/s. Consolidated Pneumatic Tool Co. (India) Ltd., 301/302, Lal Bahadur Shastri Marg, Bombay-400080.
	NON-MEMBER CONVENER
	Joint Director (Ex-officio), Export Inspection Council, Aman Chambers, 113, M. Karve Road, Bombay-4.

2. The quorum of the panel shall be three.

[No. 6/37/72-E&P]

K.V. BALASUBRAMANIAN Deputy Director

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1975

का० आ० 1817.—सर्वश्री पंजाब ट्रैक्टर लि० नं० 10 सेक्टर 9-ए चन्डीगढ़ को 15,400 रुपए (पन्द्रह हजार चार सौ रुपए मात्र) का आयात लाइसेंस सं० आई०/डी०/1405991 टी० आ० आर०/53/एच/39-40 दिनांक 1-1-75 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई। अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाई गई थी। इसका शून्य रुपए के लिए उपयोग किया गया था और दिनांक 14-2-75 को इस में शेष 15,400 रुपए थे।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ आयुक्त चन्डीगढ़ से एक प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उप-धारा 9 (सी० सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री पंजाब ट्रैक्टर लि०, चन्डीगढ़ को जारी किए गए लाइसेंस सं० आई०/डी०/1405991/टी०/आ०/आर०/53/एच/39-40 दिनांक 1-1-1975 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति भलग से जारी की जा रही है।

[संख्या पी वी टी/4/74-75 पी० एल० एस० ए]

## OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

### ORDER

New Delhi, the 26th May, 1975

S.O. 1817.—M/s. Punjab Tractors Ltd. No. 10 Sector 9-A Chandigarh were granted an import licence No. I/D/1405991/T/OR/53/H/39.40, dated 1-1-1975 for Rs. 15,400 (Rupees fifteen thousand and four hundred only). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Control copy was not registered with any Customs authorities. It was utilised for Rs. Nil and the balance available on it was Rs. 15,400 as on 14-2-1975.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Oath Commissioner Chandigarh I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Exchange Control Purposes copy of licence No. I/D/1405991/T/OR/53/H/39.40 dated 1-1-1975 issued to M/s. Punjab Tractors Ltd., Chandigarh is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. PBT/4/74-75 PLSA]

आदेश

का० आ० 1818.—सर्वश्री पंजाब ट्रैक्टर लि० नं० 10 सेक्टर 9-ए चन्डीगढ़ को 21,100 रुपए (इक्कीस हजार एक सौ रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० आई०/डी०/1405992/एस०/आई० एन०/53/एच/39-40 दिनांक 1-1-75 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाई गई थी। इसका शून्य रुपए के लिए उपयोग किया गया था और दिनांक 14-2-75 को इस में शेष 21,100 रुपए थे।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ आयुक्त चन्डीगढ़ से एक प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए, यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सी० सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री पंजाब ट्रैक्टर लि० चन्डीगढ़ को जारी किए गए लाइसेंस सं० आई०/डी०/1405992/एस०/आई०/एन०/03एच/39-40 दिनांक 1-1-75 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति भलग से जारी की जा रही है।

[सं० पी वी टी/4/74-75 पी० एल० एस० ए०]

S.O. 1818.—M/s. Punjab Tractor Ltd., No. 10 Sector 9A, Chandigarh were granted an import licence No. I/D/

1405992/S/IN/53/H/39.40 dated 1-1-1975 for Rs. 21,100 (Rupees Twentyone thousand and one hundred only). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Control copy was not registered with any Customs authorities. It was utilised for Rs. Nil and the balance available on it was Rs. 21,100 as on 14-2-1975.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Oath Commissioner Chandigarh. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Exchange Control Purposes copy of licence No. I/D/1405992/S/IN/53/H/39.40 dated 1-1-1975 issued to M/s. Punjab Tractors Ltd., Chandigarh is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. PBT/4/74-75/PLSA]

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1975

क्रा० 1819.—सर्वश्री हिन्दुस्तान इस्पात लि० भिलाई इस्पात प्लांट, भिलाई (म०प्र०) को 2,80,00,000 (दो करोड़ अस्सी लाख रुपये मात्र) का एक आयात लाइसेंस संख्या जी०/ए०/1035939/सी०यू० आर०/एच/28-29, दिनांक 13-8-68 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस आधारे पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे बताया गया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति विशाखापटनम सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत करवाई गई थी। उसका 2,18,73,265.22 रुपए के लिए उपयोग कर लिया गया था और 25-11-74 को उस में शेष 61,26,734.78 रु० था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी जिला बुरंग (म०प्र०) द्वारा एक प्रमाणपत्र के साथ एक गणपथ पत्र दाखिल किया है। तबनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई

है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री हिन्दुस्तान इस्पात लि० भिलाई इस्पात प्लांट भिलाई को जारी किए गए उक्त लाइसेंस संख्या : जी०/ए०/1035939, दिनांक 13-8-68 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या: एच० एस० एल०/26/68-69/पी०एल०एस०ए०]

एस० के० उस्मानी, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1975

S.O. 1819.—M/s. Hindustan Steel Ltd., Bhilai Steel Plant, Bhilai (M. P.) were granted an import licence No. G/A/1035939/C/UR/H/28-29, dated 13-8-1968 for Rs. 2,80,00,000 (Rupees two crores and eighty lakhs only). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Control copy was registered with the Customs authorities at Visakhapatnam. It was utilised for Rs. 2,18,73,265.22 and the balance available on it was Rs. 61,26,734.78 as on 25-11-1974.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Notary, Distt, Durg (M.P.). I am accordingly satisfied that the original Exchange Control copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended the said original Exchange Control purposes Copy of licence No. G/A/1035939 dated 13-8-1968 issued to M/s. HSL, Bhilai Steel Plant, Bhilai is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. HSL/26/68-69/PLSA]

S. K. USMANI, Dy. Chief Controller

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 23 मई, 1975

क्रा० 1820.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी०एम०/एल०-3855 जिसके व्यौरे नोबे अनुसूची में दिए गए हैं, लाइसेंसधारी की लाइसेंस को आगे जारी रखने में रुक न होने के कारण 1 अप्रैल, 1975 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
1.	सी०एम०/एल०-3855	मैसर्स कोणार्क रबर इंडस्ट्रीज लि०, सी०/7 इंडस्ट्रियल इस्टेट, कटक-3	साइकिल टायर ग्रेड II मार्का :—'हीरा'	IS : 2414-1969 साइकिल टायरों की विशिष्टि

[सी०एम०/सी०/55: 3855]

ए०के० गुप्ता, कार्यवाहक महानिदेशक

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE &amp; TECHNOLOGY

(INDIAN STANDARDS INSTITUTION)

New Delhi, the 23rd May, 1975

**S.O. 1820.** :—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulation 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L—3855 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1-4-1975 as the party is not interested to continue it further.

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Governed by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-3855	M/s. Konark Rubber Industries Ltd., C/7 Industrial Estate, Cuttack-3	Cycle Tyres Grade II Brand:—"HIRA"	IS:2414-1969 Specification for Cycle Tyres.

[CMD/55: 3855]

A.K. Gupta, Acting Director General

पूति और औद्योगिक मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1975

शुद्धि-पत्र

क्रा० प्रा० 1821.—भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या 1134 दिनांक 20-4-74 जो वस्त्र मशीनों के निर्माण अथवा उत्पादन हेतु अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद् की स्थापना करने के बारे में है और जिसे भारत के राजपत्र के भाग II खंड-3, उपखंड (ii) दिनांक 20 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित किया गया में, निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा —

19. श्री आई. बी. डत्त,  
नेविले हाउस, चौथी मंजिल,  
ग्राहम रोड, बेल्लार्ड एस्टेट,  
बम्बई-400038

[सं० 2-2/71-एच० एम०]

पी० आर० दासगुप्ता, उप-सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 31st May, 1975

## CORRIGENDUM

**S.O. 1821.**—In the order of the Government of India, Ministry of Heavy Industry No. 1134 dated 20-4-1974, establishing a Development Council for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of Textile Machinery, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 20th April, 1974 the following amendment shall be made :—

19. Shri I. B. Dutt,  
Neville House, 4th Floor,  
Graham Road,  
Ballard Estate,  
Bombay-400038.

[No. 2-2/71-HM-I]

P. R. DASGUPTA, Dy. Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1975

क्रा० प्रा० 1822.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम

और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3236 तारीख 19-11-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का माना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देनी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्देश किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के अन्तर्गत और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघर्षों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

डी एस सं० के० 134 से जी जी एस-8 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात	तालुका : कलोल	जिला : महसना			
गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर एं	आर ई	सेंटी-	नियर
कलोल	673/1	0	11	72	
	669/2	0	06	00	

[सं० 12016/10/74-एल एण्ड/एल]

## MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 24th May, 1975

**S.O. 1822.**—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3236 dated 19-11-1974 under



sub-section (1) of section 3 of the Petroleum pipelines (Acquisition of Right of Users in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

For Laying Pipeline From D.S. No. K-134 to G.G.S. 8

State : Gujarat Taluka : Kalol District : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
KALOL	673/1	0	11	72
	669/2	0	06	00

[No. 12016/10/74-L&L/VI]

क्र० घा० सं० 1823.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का प्रजन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना क्र० घा० सं० 3237 तारीख 19-11-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

जी एस एन के 54 से जी जी एस/सी टी एफ का बी तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात तालुका : कावी जिला : मेहसाना

गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	एअर ई सेंटी-	नियर
चलासन	82/1	0	09	12
	81/2	0	09	24
	81/1	0	09	96
कार्ट ट्रैक 81 तथा 92 के बीच		0	01	00
	91/2	0	02	25
	93	0	27	60

[सं० 12016/10/74-एन एण्ड एन/VI]

S.O. 1823.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S. O. No. 3237 dated 19-11-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

For Layin pipe line from D.S.N.K 54 to GGS/C T F kadl

State:Gujarat Taluka: Kadi District:Mehsana

Village	Survey No.	Hectare.	Are.	Centiare.
Chalasan	82/1	0	09	12
	81/2	0	09	24
	81/1	0	09	96
	Cart Track	0	01	00
	Between 81 & 91			
	91/2	0	02	25
	93	0	27	60

[No. 12016/10/74-L&L/VI]

क्र० प्रा० 1824.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 60) के धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना क्र० प्रा० सं० 3239 तारीख 19-11-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देनी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करते हैं कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, संघकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाश की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

डी० एस० एन० के-61 से जी जी एस/सी टी एफ कादी

गाँव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए	आर	ई	सेंटीयर
चलासन	91/1-ए	0	05	64		
	91/1-बी	0	03	60		
	92	0	03	60		
	93	0	06	48		

[सं० 12016/10/74-एल एण्ड एल/VIII]

टी० पी० सुब्रह्मण्यम, धवर सचिव

S.O. 1824.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S. O. No. 3239 dated 19-11-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

For Laying Pipeline From D.S. NK-61 to GGS/CTF Kadl.  
State:Gujarat Taluka:Kadi District:Mehsana

Village	Survey No.	Hectare.	Are.	Centiare.
Chalasan	91/1-A	0	05	64
	91/1-B	0	03	60
	92	0	03	60
	93	0	06	48

[No. 12016/10/74-L&L/V III]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

#### निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जून, 1975

क्र० प्रा० 1825.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिकारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ (I) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, और यह भी निदेश देती है कि वह उक्त सारणी के स्तम्भ (II) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

#### सारणी

अधिकारी का पामिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
I	II
कार्यपालक इंजीनियर, भोपाल, केन्द्रीय प्रभाग, केन्द्रीय लोक संकर्म विभाग, भोपाल	भोपाल केन्द्रीय प्रभाग, केन्द्रीय लोक संकर्म विभाग की अधिकारिता के भीतर स्थित केन्द्रीय लोक संकर्म विभाग प्रशासनिक अधिकारिता के अन्तर्गत स्थान।

[क्र० सं० 21012 (17)/73-पोल० 3]

एच० आर० गोयल, उप सम्पदा निदेशक (वालिसी)

#### MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 6th June, 1975

S.O. 1825.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being a gazetted officer of Government to be estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that he shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officer by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of the category of the public premises specified in column (II) of the said Table.

## TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(I)	(II)
Executive Engineer, Bhopal Central Division, Central Public Works Department, Bhopal.	Premises under the administrative control of the Central Public Works Department situated within the jurisdiction of Bhopal Central Division, Central Public Works Department.

[File No. 21012(17)/73-Pol. III]

H.R. GOEL, Deputy Director of Estates (Policy)

श्रम मंत्रालय

प्रारंभ

नई दिल्ली, 7 मई, 1975

का० प्रा० 1826.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा-  
बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमि-  
टेड, डाकबर रानावव, जिला जुनागढ़ के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों  
और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये  
निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)  
की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधि-  
करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० सी० शाह  
होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त  
औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

“क्या मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड, डाकबर रानावव, जिला जुनागढ़  
के प्रबन्धतन्त्र द्वारा पत्थर खनन, रानावव के मिस्त्री श्री के० बीरू ठाकुर की  
सेवायें 23 अक्टूबर, 1974 से समाप्त करना न्यायोचित और वैध  
है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?”

[संख्या एल०-29011/22/75-डी० प्रो०-3 (बी०)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 7th May, 1975

S.O. 1826.—Whereas the Central Government is of opinion  
that an industrial dispute exists between the employers in  
relation to management of Messrs Tata Chemicals Limited,  
Post Office Ranavav, District Junagadh, and their workman  
in respect of the matters specified in the Scheduled hereto  
annexed;

And whereas the Central Government considers it desir-  
able to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by  
section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10  
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central  
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with  
Shri M. U. Shah as Presiding Officer with headquarters at  
Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to  
the said Industrial Tribunal.

## SCHEDULE

“Whether the termination of services of Shri K. B.  
Thakur, a Mechanic of Stone Quarry, Ranavav,  
with effect from the 23rd October, 1974 by the  
management of Messrs Tata Chemicals Limited,  
Post Office Ranavav, District Junagadh, justified and  
legal. If not, to what relief the workman is entitled?”

[No. L-29011/22/75-D. O. 3(B)]

प्रारंभ

नई दिल्ली, 12 मई, 1975

का० प्रा० 1827.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा-  
बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में आलुघाटा बलुआ पत्थर खानों  
के स्वामी श्री रामकृष्ण वर्मा पुत्र श्री नरसिंह लाल कोली निवासी जल-  
वारा, तहसील किशनगंज, जिला कोटा, नियोजक और उनके कर्मकार के  
बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये  
निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)  
की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की  
धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर  
को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री रामकृष्ण वर्मा पुत्र श्री नरसिंह लाल कोली, निवासी जलवारा,  
तहसील किशनगंज जिला कोटा में, आलुघाटा बलुआ पत्थर की खानों,  
तहसील किशनगंज, जिला कोटा में श्री धन्ना लाल वर्मा पत्थर कर्तक  
की सेवायें 20 जुलाई, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है?  
यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल० 29011/24/75-डी० प्रो०-3 (बी०)]

ORDER

New Delhi, the 12th May, 1975

S.O. 1827.—Whereas the Central Government is of opinion  
that an industrial dispute exists between the employers Shri  
Ramkrishan Verma son of Shri Narsinghlal Koli, Resident  
Jalwara, Tehsil Kishonganj, District Kota, owner Alughata  
Sand Stone Mines and their workmen in respect of the matters  
specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desir-  
able to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by  
clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial  
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government  
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central  
Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under  
section 7A of the said Act.

## SCHEDULE

Whether the action of Shri Ram Kishan Verma, son of  
Shri Narsinghlal Koli, Resident of Jalwara,  
Tehsil Kishanganj in the District of Kota in ter-  
minating the services of Shri Dhannalal Verma,  
Stone Cutter in Alughata Sand Stone Mines, Tehsil  
Kishanganj, District Kota with effect from the  
20th July, 1974, is justified? If not, to what  
relief is the said workman entitled?

[No. L-29011/24/75-D. O. 3(B)]

का० प्रा० 1828.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे  
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री बालचन्द्र कलाल,  
जिला कोटा, तहसील किशनगंज, जिला कोटा, नियोजक और उनके कर्मकार के

डाकघर बुधपुरा, जिला बून्दी (राजस्थान) की बलुआ पत्थर खान, डाकघर बुधपुरा, जिला बून्दी के प्रबन्ध तन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

क्या श्री बाल खन्ना कलाल डाकघर बुधपुरा, जिला बून्दी (राजस्थान) की बुधपुरा बलुआ पत्थर खान में नियोजित कर्मचारों की सेवा वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के लिये मजदूरी के 20 प्रतिशत की की दर से लाभ सहभाजन बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिये बोनस की किस मात्रा के हकदार हैं?

[संख्या एल०-29011/27/75-डी० ओ०-3 (बी०)]

एस० एच० एस० इयर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

**S.O. 1828.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Budhpura Sand Stone Mines, Post Office Budhpura, District Bundi of Shri Balchandra Kalal, Post Office Budhpura, District Bundi (Rajasthan) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Budhpura Sand Stone Mine of Shri Balchandra Kalal, Post Office Budhpura, District Bundi (Rajasthan) for payment of profit sharing bonus at the rate of 20 per cent of wages for the accounting years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 is justified? If not, to what quantum of bonus are the said workmen entitled for each of these years.

[No. L-29011/27/75/D. O. 3(B)]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 1975

का० भा० 1829 —यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में एयर इंडिया, बम्बई के प्रबन्ध तन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

क्या एयर इंडिया बम्बई के प्रबन्धतन्त्र की, श्री एन० एन० वैशम्पायन को पहली जून, 1955 से कनिष्ठ लिपिक के रूप में पुष्ट करने की कार्रवाई वैध और न्यायोचित थी। यदि उत्तर सकारात्मक नहीं है तो क्या इससे श्री बी० एस० राने, अन्य कनिष्ठ लिपिक, की ज्येष्ठता का ह्रास हुआ है, और यदि हाँ, तो व्यक्ति कर्मकार, श्री बी० एस० राने किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल०-11011/(24)/74-एल आर०-3/डी० 2 बी०]

हरबंस बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

#### ORDER

New Delhi, the 8th May, 1975

**S.O. 1829.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Air India, Bombay, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

Whether the action of the management of Air India, Bombay, in confirming Shri N. N. Vaishampayan as a Junior Clerk with effect from 1-6-1955 was legal and justified? If the answer is not in the affirmative, whether this has caused retrogression of seniority of Shri V. S. Rane, another Junior Clerk, and if so, to what relief is the aggrieved workman, Shri V. S. Rane entitled?

[No. L-11011 (24)/74-LR. III/D. ii(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

#### आदेश

का० भा० 1830.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स जनरल सुपरिण्टेन्डेंस कम्पनी (इंडिया) (प्राइवेट) लिमिटेड, वास्को-डा-गामा के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2 बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

1. (क) क्या मैसर्स जनरल सुपरिण्टेन्डेंस कम्पनी (इंडिया) (प्राइवेट लिमिटेड, वास्को-डा-गामा, गोवा के प्रबन्धतन्त्र की, अपने सैम्पलिंग

कर्मचारियों को उस अन्तरिम भत्ते के लाभ को, जो पत्तन तथा डाक कर्म-  
कार की तीन फेडरेशनों और मौवहून और परिवहन मंत्रालय के बीच  
19-1-75 को हुये समझौते के अनुसार अन्य पत्तन तथा डाक कर्मचारों  
को वसूल किया जा रहा है, अनुवृत्त न करने की कार्यवाही न्यायोचित है?

(ख) यदि नहीं तो, वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?

2. (क) क्या मैसर्स जनरल सुपरिण्डेंस कंपनी (इंडिया) (प्राई-  
वेट) लिमिटेड, वास्को-डा-गामा, गोवा के सैम्पलिंग कर्मचारों की निम्न-  
लिखित सवों की बाबत मांग न्यायोचित है;

(i) मीरु गोवा डाक श्रम बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मचारों के  
सम्बन्ध में प्रचलित वरों पर राशि बेटेज भत्ते और धुलाई  
भत्ते का संवाय;

(ii) सैम्पलिंग सहायकों के लिये छुट्टी सुविधाओं में वृद्धि।

(ख) यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल०-36011/7/75-डी०-4(ए०)]

**S.O. 1830.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs General Superintendence Company (India) (Private) Limited, Vasco-da-Gama and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

1. (a) Whether the management of Messrs General Superintendence Company (India) (Private) Limited, Vasco-da-gama, Goa, are justified in not granting to their sampling workmen the benefit of interim relief which is being paid to other Port and Dock workers, as per the agreement reached on 19-1-1975 between the three Federations of Port and Dock workers and the Ministry of Shipping and Transport?

(b) if not, to what relief are they entitled?

2. (a) Whether the demands of the sampling workmen of messrs General Superintendence Company (India) (Private) Limited Vasco-da-gama, Goa, in respect of the following items are justified:

(i) Payment of Night Weightage allowance and washing allowance at the rates prevailing in respect of the Registered Dock Workers of Marmugea Dock Labour Board;

(ii) Increase in the leave facilities for the Sampling Assistants.

(b) If so, to what relief are the workmen entitled?

[No. L-36011/7/75-DIV (A)]

का० प्रा० 1831—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस  
उपाख्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स इतालब (गोवा)  
(प्राइवेट) लिमिटेड, मार्गाओ (गोवा) के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध  
नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान  
है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये  
निर्दिष्ट करना बांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)  
की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम  
की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण  
सं० 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्दिष्ट करती है।

#### अनुसूची

क्या मैसर्स इतालब (गोवा) (प्राइवेट) लिमिटेड, मार्गाओ (गोवा) के प्रबन्ध-  
तंत्र की सर्वश्री गणेश सतुरदेकर, विष्णु विथल खोबरेकर, दामोदर अंकुश  
कोरकर, दामोदर पांडुरंग विचोलकर, कृष्णा मंजुनाथ होमावाकर, शांभु-  
रामाभाटकर और सर्वश्रीमती राधाबाई राधाकृष्णन कुबाल, दुर्गाबाई राजा-  
राम कोचनाकर, सुमति भंगुएश पेदनेकर, विजयारामा जोनगेकर, हरिबाई  
केशव सतुरदेकर और भागीरथी नारायण मुजेकारलि, नमूना मजदूरों  
की पुष्टि करने से इनकार करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो  
उक्त कर्मकार किस अनुतोष और किन प्रसुविधाओं के हकदार हैं?

[संख्या एल-36011/8/75-डी०-4(ए)]

नव लाल, अनुभाग अधिकारी (बिरोष)

#### ORDER

**S.O. 1831.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Italab (Goa) (Private) Limited, Margao (Goa) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Italab (Goa) (Private) Limited, Margao (Goa), in refusing confirmation to Sarvashri Ganesh Saturdekar, Vishnu Vithal Khobrekhar, Damodar Ankush Kerkar, Damodar Pandurang Dicholkhar, Krishna Manjunath Honawarkar, Shamu Rama Matkar, and Sarva Srimati Radhabai Radhakrishnan Kubal, Durgabai Rajaram Kochnekar, Sumati Manguesh Pednekar, Vijaya Rama Dongekar, Haribai Keshav Saturdekar and Bhagirathi Narain Majurekarin, Sample Boys, is justified? If not, to what relief and benefits, are the said workmen entitled?

[No. L-36011/8/75-D-IV(A)]

New Delhi, the 2nd June, 1975

**S.O. 1832.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st May, 1975.

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

PRESENT:

Shri E. K. Moidu—Presiding Officer.

Reference No. 6 of 1975

**PARTIES :**

Employers in relation to the Calcutta Port Commissioners, Calcutta.

**AND**

Their Workmen

**APPEARANCE :**

On behalf of Employers—Shri S. M. Banerjee, Labour Adviser and Industrial Relations Officer, with Shri S. P. Naha, Deputy Labour Adviser and Industrial Relations Officer, Calcutta Port Trust.

On behalf of Workmen—Shri Prasanta Kumar Datta, General Secretary, Calcutta Port & Dock Workers Union.

State : West Bengal.

Industry : Port & Dock.

**AWARD**

By Order No. L-32012/12/74-P&D/CMT/D-IVA, dated 16th January, 1975, the Government of India in the Ministry of Labour, referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the demand of the Stretcher Bearers attached to the Dock Hospital of Calcutta Port Commissioners for Tiffin Allowance for the days they come in contact with T.B. Patients of the Isolation Ward of the Dock Hospital is justified? If so, to what relief are the workers entitled?"

2. Some 21 stretcher bearers attached to the Dock hospital under the Calcutta Port Trust claim tiffin allowance at the rate .75 paise per day on account of the fact that they have to work with patients afflicted with infectious disease and as such they require extra food as protection against such diseases. They state that they carry patients when disease is to be diagnosed and therefore they come in contact with the patients suffering from infectious diseases for which they should take preventive measures as they have to always such patients within the course of their performance of duties both in the Chest clinic as well as in the isolation ward. According to them the tiffin allowance was allowed in the first instance to all these employees working in the dock hospital but later by a resolution of the Port Commissioners the tiffin allowance was extended to Dhobis, Cooks and Cook-mates, but no such benefit was given to the stretcher bearers. They state that the possibility of infection of the disease is involved while they carry the patients to the T.B. ward and back from the hospital to other departments for examination and treatment.

3. The management of the Port Trust alleges that the basis on which tiffin allowance was granted to certain categories of staff was that they were continuously deputed for duty in the isolation ward or in the Chest clinic and that the stretcher bearers are not required to work in the isolation ward or in the chest clinic continuously. They state that the stretcher bearers generally come in contact with patient only during the transit of such patients from and to hospital. The incident of general patients detected later on to be patient afflicted with T.B. is almost negligible. Besides they state that for carrying patients suffering from T.B. and other infectious diseases occasionally the chances of contacting infectious diseases are very little. They contend that granting tiffin allowance for such purpose would be a deviation from the rule laid down and is likely to open a flood gate of such untenable claims.

4. The issue of payment of tiffin allowance to the class III and class IV employees of the dock hospital under the Port Commissioners was taken up first by the Calcutta Port Shramik Union. Under the terms of settlement between the union and the management it was decided that class III and Class IV employees continuously deputed to work in the isolation ward in the dock hospital would be paid a tiffin allowance of .75 P per day for the period so deputed to work in such wards. This allowance was accordingly sanctioned with effect from 1-6-1959. However, it was clarified that employees who are not so deputed are not eligible for the said allowance. This concession was further extended to class III and class IV staff attached to the Chest clinic of dock hospital with effect from 15-5-63.

5. The demand for payment of tiffin allowance to the stretcher bearers, dhobis and other such employees of dock hospital was raised by the union in 1970. It was agreed to extend the grant of tiffin allowance to the dhobis attached to the dock hospital considering that he is to wash clothes of the patients of isolation wards more or less on continuous basis and is therefore exposed to infection. So, tiffin allowance of .75 P was granted to the dhobis working in the dock hospital with effect from 11-11-1970. The issue of payment of tiffin allowance to stretcher bearers was left open though it was stated that the management had brought a resolution to the notice of the union : Nurses, laboratory assistants, Pharmacists, Dressers and Stretcher bearers who may be required to work in the isolation ward of the hospital occasionally or who may come in contact of T.B. patients in the course of their normal duties are not eligible for tiffin allowance. This order was the subject matter of an arbitration by Sri Mahipati the then Deputy Labour Commissioner (Central). The result of the arbitration was the rejection of the demand made by these employees for tiffin allowance. Any way, the matter was taken up by the union with the management. In spite of attempt to conciliation the matter could not be settled and hence the reference.

6. The argument on behalf of the management is that the tiffin allowance is paid only to persons who are deputed to work in the dock hospital in charge of the T.B. patients and not to others. But that rule was not strictly followed when allowance was sanctioned in favour of dhobis. They are, as a matter of fact, not deputed to work in the hospital. Another argument is that by carrying patients suffering from T.B. and other infectious diseases occasionally the chances of contacting infectious diseases are very little. This argument does not appear to be correct. It requires only a second for any person to be infected with T.B. if he comes in contact of that patient. It does not appear to be necessary that persons to be infected with the disease they should be in continuous duty with the patients. The fact that the stretcher bearers do not work continuously within the dock hospital is not an argument to deny tiffin allowance to them.

7. It is in evidence that there are T.B. patient beds in dock hospital as well as 25 similar beds reserved for such patients of the Port Trust in K. S. Roy T.B. Hospital and Kanchrapara T.B. Hospital. The stretcher bearers are required to accompany the patient when they are sent to different hospitals in ambulance. Ambulatory patients report to the different T.B. hospitals for admission of their own. The number of T.B. patients who are to be removed from the dock hospital for admission or to be brought from other T.B. hospital to dock hospital for admission and treatment, by ambulance are enumerated in the letter of the Chief Medical Officer, Dock Hospital, Calcutta Port Trust. It is evident from these circumstances that the stretcher bearers also come in contact with the patients whenever they carry those patients in stretchers. It is therefore right that they are also paid a tiffin allowance of .75 P whenever they are so employed.

8. In the result, the reference is answered in favour of the workmen by allowing them tiffin allowance at the rate of .75 P per head for the days on which they carry patients from the dock hospital to other T.B. hospitals and bring them back to the dock hospital as well as on the days on which they carry T.B. patients to and fro the isolation ward of the dock hospital and Chest clinic or other places for treatment. This order shall come into effect from this date.

I pass an award accordingly.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

Dated, Calcutta,

The 26th May, 1975.

[No. L-32012/12/74-P&D/CMT/D-IV (A)]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 1975

क्र० आ० 1833.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिय कोल लिमिटेड की कुजामा कोलियरी, डाकघर झरिया, जिला धमबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कुजामा कोलियरी, डाकघर झरिया, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र का, श्री पूना मल्लाह, साधारण मजदूर को 20 जून, 1974 से काम से रोकना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-20012/133/74-एल० प्रार० 2/डी-3ए]

New Delhi, the 13th May, 1975

**S.O. 1833.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kujama Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharla, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, Constituted under Section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

Whether the management of Kujama Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharla, District Dhanbad, are justified in stopping Shri Puha Mallah, General Mazdoor, from work with effect from 20th June, 1974? If not, to what relief is the said workman entitled".

[No. L-20012/133/74-LR II/D.III.A]

का० प्रार० 1834.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोल माईन्स प्रचारिटी लिमिटेड की शामपुर कोलियरी, डाकघर निसाचट्टी (धनबाद) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

क्या मैसर्स कोल माईन्स प्रचारिटी लिमिटेड की शामपुर कोलियरी, डाकघर निसाचट्टी, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र की, सर्वश्री (1) परसु सोईन (2) सुकुर बेहरा, (3) भास्कर गौरा, (4) चन्द्रा दाकुआ, (5) सुरेन्द्र बेहरा, (6) भूषण पोलै, (7) लोकनाथ प्रधान, (8) अभिमन्यु गौरा, (9) बांचा सेठी और (10) पानू दाकुआ, खदान खनिकों को 15-6-74 से काम न देने की कार्यवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[सं० एल 20012/112/74-एल० प्रार०-2/डी-3(ए)]

एल० के० नारायण, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

**S.O. 1834.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Shampore Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti (Dhanbad), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, Constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

Whether the action of the management of Champore Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad in refusing work to Sarvashri (1) Parsu Soin, (2) Sukur Behra, (3) Bhaskar Goura, (4) Chandra Dakua, (5) Surendra Behra, (6) Bhushan Pollai, (7) Loknath Pradhan, (8) Abhimanu Goura, (9) Banacha Sethi and (10) Panchu Dakua. Quarry Miners with effect from 15-6-1974, is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

[No. L-20012/112/74-LR II/D.III A]

New Delhi, the 31st, May, 1975

**S.O. 1835.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the Industrial dispute between the employers in relation to the Management of Central Coal Washeries Organisation of Messrs Hindustan Steel Limited, Ispat Nagar, Dhanbad, and their workmen which was received by the Central Government on the 27th May, 1975.

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

##### PRESENT :

Shri K. K. Sarkar, Judge,  
Presiding Officer.

Reference No. 27 of 1973

In the matter of an industrial dispute u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

##### PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Coal Washeries Organisation of Messrs Hindustan Steel Limited, Ispat Nagar, Dhanbad.

#### AND

Their workmen

##### APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri T. P. Choudhury,  
Advocate.

On behalf of the workmen—Shri P. K. Bose, Advocate.

State : Bihar.

Industry : Coal

Dhanbad, the 23rd May, 1975

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation in the Department of Labour & Employment being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Coal Washeries Organisation of Messrs Hindustan Steel Limited, Ispat Nagar, Dhanbad and their workmen, by their order No. L-2012/57/73-LRII dated 1st September, 1973 referred the same to this Tribunal for adjudication upon the issue as stated in the schedule below :

#### SCHEDULE

"Whether the demand of Coal Washeries Workers' Union, Post office Patherdih, District Dhanbad to upgrade the post of Senior Assistant (S.T.) attached to Washery Manager, Patherdih Coal Washery of Messrs Hindustan Steel Limited, Post office Patherdih (Dhanbad) to that of Confidential Assistant in the scale of Rs. 450-720 and the present incumbent Shri D. R. Bhattacharjee should be designated as such and placed in the scale of Rs. 450-720 with effect from the 7th April, 1972 is justified? If so, to what relief is the concerned workman entitled and from which date?"

The workmen come with the following case. The Central Coal Washeries Organisation is a constituent unit of Hindustan Steel Limited and Patherdih Coal Washery is one of the plants of the aforesaid management located at Patherdih in the district of Dhanbad. The concerned workman Shri D. R. Bhattacharjee has been working in the capacity of Senior Assistant (S/T) to the Washery Manager, Patherdih Coal Washery when the Washery Manager was drawing a salary of Rs. 1450-1750 P.M. With effect from 7-4-1972 the management have upgraded the post of Washery manager and the salary has been revised to Rs. 1550-1950. According to the policy laid down by Hindustan Steel Limited, all officers drawing a salary in the scale of Rs. 1550-1950 have staff designated an Confidential Assistant in the grade Rs. 450-720. The job performed and responsibility undertaken by the concerned workman is that of a confidential assistant but the management have denied him the designation and scale of pay of a confidential assistant. The workmen duly raised an industrial dispute with the employer in this respect. The employer comes with the case—the scale of pay enjoyed by the stenographers attached to the officers has no relation with the pay scale of the officer with whom a stenographer is attached. The posts of office staff of the different offices/units of the Central Coal Washery Organisation were sanctioned as per study conducted by the O & M Organisation at the head office of the Hindustan Steel Limited at Ranchi and there is no reason to change the pattern that has been set up in respect of Patherdih Washery or in respect of other washeries and departments. It is denied that all officers of the company in the scale of Rs. 1550-1950 have been provided with confidential assistants in the scale of Rs. 450-720. The Deputy Superintendent attached to the Central office is in the pay scale of Rs. 1550-1950 and he has been provided with a confidential assistant in the scale of Rs. 450-720. The Controller of Coal Supplies is in the scale of Rs. 1550-1950 but he has not been provided with any confidential assistant. On the other hand, the Senior Personnel Officer who is in the scale of 1250-1550 has been provided with a senior stenographer. The senior assistants (S.T.) attached to the washery managers are in the scale of Rs. 340-589 which according to their nature of work has not only been found to be sufficient by the scientific work study of the O & M Division but it is on the generous side. Even though the pay scale of the washery managers has been revised from Rs. 1450-1750 to 1550-1950 there has not been any change in the nature of work of his post nor of his stenographer. It is maintained that if the demand of the workman in relation to Patherdih Coal washery is accepted it will open a flood-gate of similar demands from all other officers in other washeries and central office.

The demand in respect of the concerned workman is based mainly on two grounds. First, the scale of pay of the washery manager at Patherdih coal washery has been changed from Rs. 1450-1750 to Rs. 1550-1950 and according to the policy followed by Hindustan Steel Ltd. officers in the above revised scale are entitled to have a confidential assistant. Secondly, with the change of the scale of pay of the washery manager as above the work load and responsibility of the concerned workman who is working as a senior assistant (S.T.) to the washery manager have also increased. The management denies that all officers in the revised pay scale of Rs. 1550-1950 should have a confidential assistant. It all depends upon the work load and nature of table work of the officers concerned and it is never an accepted policy of the H.S.L. to provide confidential assistant to all officers in the revised scale of Rs. 1550-1950. The management's further contention is that with the revision of pay scale the work load and the nature of work of the washery managers have not changed and accordingly the work load and nature of work of the senior assistants have not also increased. The concerned workman Shri D. R. Bhattacharjee examined as WW. 1 says that in other units of Hindustan Steel Ltd. the scale of the senior assistants have been upgraded with the upgrading of the scale of the officer to whom he is attached to Rs. 1550-1950. In the same breath he says that not all the officers in scale of Rs. 1550-1950 have been provided with confidential assistants in the scale of Rs. 450-720. There are other coal washeries in Bhujudi and Dugda under H.S.L. having separate washery managers. WW. 1 admits that all the washery managers have been provided with a senior assistant (Steno) and not confidential assistants. WW. 1 also admits in his evidence that inspite of the revision of their scale of pay the washery managers are doing the same work as they were doing before and the senior assistants under them are also doing the same work as before. The workman has not adduced satisfactory evidence before this Tribunal in support of his contention that officers in the revised scale of Rs. 1550-1950 are entitled to get confidential assistants or have actually got confidential assistants under them. Shri K. P. Sinha who is the Personnel Officer attached to the Central Washery Organisation of Hindustan Steel Ltd. examined as MW. 1. says that an officer in the scale of Rs. 1550-1950 is not entitled to get a confidential assistant but it is officers who are in the scale of Rs. 1750-2150 who are entitled to get confidential assistants. In support of his evidence he relies on a letter of the Hindustan Steel Ltd. head office Ranchi dated 12-6-1972 to the Personnel Officer of the Central Coal Washery Organisation at Dhanbad, (Ext. M2). It is stated therein that in the head office of the Hindustan Steel Ltd. at Ranchi confidential assistants are provided to the officers in the scale of Rs. 1750-2150. It is also stated therein that the posting of confidential assistant is subject to creation/sanction of posts by the competent authority. Thereafter from another letter of the Hindustan Steel Ltd. at Ranchi (Ext. M3) it appears that the competent authority approved revised sanction for washeries Central Office and Finance Department and the distribution of the posts have been shown in the annexures attached to Ex. M3. It appears from the annexure attached to Ext. M3 that so far as the coal washeries at Dugda, Bhujudi and Patherdih are concerned there was no revised sanction for the post of confidential assistants. It further appears that in the central office there was revised sanction of two confidential assistants in the scale Rs. 450-720 the distribution of which was one to the Chief Personnel Officer and one to the Deputy Superintendent. The Deputy Superintendent is in the scale of Rs. 1550-1950 but still he has been provided with a confidential assistant as the Hindustan Steel Ltd. considers the post to be an important one in view of the fact that his job is to correlate and co-ordinate the activities of all the washeries and such post is filled up from the senior most washery managers. It is for the Hindustan Steel Ltd. to decide as to which officers should be provided with confidential assistants depending upon the importance and nature of work of the officer concerned irrespective of the scale of pay he is attached to. On the authority of the documents as discussed above it is clear that according to the decision of the competent authority of Hindustan Steel Ltd. officers in the revised scale of Rs. 1550-1950 are not entitled to have a confidential assistant except in one or two cases depending upon its importance. It is also clear therefrom that according to the revised sanction of the competent authority of Hindustan Steel Ltd. not a single coal washery manager in all the four coal washeries of Hindustan Steel Ltd. is entitled to have a confidential assistant though they are in the scale of Rs. 1550-1950. It is not for this Tribunal to interfere



in the affairs of the competent authority of the Hindustan Steel Ltd. and to dictate which and which officers should be provided with a confidential assistant. It is their internal administration and they must be allowed to carry on their administration according to the best of their judgment. When the existing facts and circumstances do not allow a confidential assistant to be attached to a washery manager the question remains if this Tribunal should call up the management of the Patherdih Coal washery to create the post of a confidential assistant and attach it to the washery manager of Patherdih Coal Washery. It is not within the jurisdiction of this Tribunal to assess the importance and nature of work of a coal washery manager in view of the terms of the Reference and force the creation of a post of confidential assistant for a Patherdih coal washery. The other test as alleged by the concerned workman is that his work load and responsibility have been increased. This test does not stand to scrutiny in view of Shri Bhattacharjee's own evidence before me that with the revision of scale of pay of coal washery manager there has been no change in the work of either the coal washery manager or his senior assistant. Now even if for argument's sake it is held that the post of the senior assistant under the coal washery manager, Patherdih should be upgraded to that of a confidential assistant, the question remains if that post should automatically go to the concerned workman. I am afraid not. It appears from Ext. M1 that there was a memorandum of settlement between the management and the workmen represented by the union on 22-11-1971 with regard to promotion policy of the ministerial staff and it appears from para VII that all vacancies in the post of confidential assistants will be filled up by selection from among eligible departmental candidates and the method of selection will be based on seniority (40 per cent marks), service record (30 per cent marks) and interview (30 per cent marks) and the employees found suitable for promotion will be graded on the basis of seniority. This agreement was for 2 years but there is nothing to show that it has been terminated by either side or any new promotion policy has been adopted. So the appointment of confidential assistants depend upon a selection from among the eligible departmental candidates who will be given marks according as they fare in the selection. It will be premature to suppose that Shri Bhattacharjee the concerned workman will top the list in any such selection that might be held so that he can claim to be straight-away posted as confidential assistant in advance. Whichever way the concerned workman may choose to go it doesn't help him. It will therefore appear that the demand of Coal Washeries Workers Union either in respect of ungrading the post of senior assistant in the scale of Rs. 450-720 or in respect of placement of the concerned workman in the said post in the scale of Rs. 450-720 has not been made out.

In the result the demand of the Coal Washeries Workers Union, Post office Patherdih, District Dhanbad to upgrade the post of Senior Assistant (S.T.) attached to washery manager, Patherdih of Messrs Hindustan Steel Limited, Post office Patherdih, Dhanbad to that of the confidential assistant in the scale of Rs. 450-720 and that the present incumbent Shri D. R. Bhattacharjee should be designated as such and placed in the scale of Rs. 450-720 with effect from 7th April, 1972 is not justified and the concerned workman is entitled to no relief.

This is my award.

K. K. SARKAR, Presiding Officer,  
[No. L-2012/57/73/LRII/D III A]  
L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 5 जून, 1975

का० प्रा० 1836.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उप खंड (vi) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना (भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 3460 दिनांक 13 दिसम्बर, 1974) द्वारा दिल्ली दुग्ध स्कीम के अधीन दुग्ध प्रदाय के लिये उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 22 दिसम्बर, 1974 से छः मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उप खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 22 जून, 1975 से छः मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस०-11025/25/74-डी० के०-आई० ए०]

भार० पी० नरुला, अवर सचिव

New Delhi, the 5th June, 1975

S.O. 1836.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section (2) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), (being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 3460 dated the 13th December, 1974) the industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from 22nd December, 1974;

And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section (2) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from 2nd June, 1975.

[F. No. S-11025/25/74 DKIA]

R. P. NARULA, Under Secy.

